IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

द्वि-दलीय राजनीति बनाम तीसरा विकल्प: राजस्थान की दलीय प्रणाली की एक विस्तृत समीक्षा

संजय कुमार चौधरी*[1] एवं डॉ. अजीत[2]

[1]पीएचडी शोधार्थी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।

[2]पीएचडी गाइड, राजकीय कमला मोदी कन्या महाविद्यालय, नीमकाथाना।

शोध सार

पृष्ठभूमि : राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था ऐतिहासिक रूप से एक सुदृढ़ 'द्वि-दलीय प्रणाली' रही है, जहाँ सत्ता मुख्य रूप से कांग्रेस और भाजपा के इर्द-गिर्द घूमती है। हालाँकि, हाल के वर्षों में 'राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी' (RLP) और 'भारत आदिवासी पार्टी' (BAP) जैसे क्षेत्रीय दलों के उभार ने इस स्थापित व्यवस्था के समक्ष एक वैचारिक और चुनावी चुनौती प्रस्तुत की है।

उद्देश्य : इस व्यवस्थित समीक्षा का मुख्य उद्देश्य राजस्थान में एक स्थायी 'तीसरे विकल्प' की राजनीतिक व्यवहार्यता, क्षेत्रीय दलों की 'जातिगत लामबंदी' (विशेषकर जाट अस्मिता), और कृषि संकट के चुनावी प्रभावों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है।

कार्यप्रणाली : PRISMA (2020) दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए, यह अध्ययन राजस्थान की चुनावी राजनीति और दलीय प्रणाली पर केंद्रित 6 उच्च-स्तरीय पीयर-रिव्यूड शोध पत्रों का गुणात्मक विषयगत संश्लेषण प्रस्तुत करता है।

परिणाम : शोध के परिणाम स्पष्ट करते हैं कि राजस्थान में क्षेत्रीय दलों का उभार मुख्य रूप से विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों में केंद्रित 'सबाल्टर्न' (हाशिए के) समूहों और 'प्रबल जातियों' के राजनीतिक असंतोष का परिणाम है। यद्यपि कृषि संकट और युवा बेरोजगारी ने इन दलों को एक प्रारंभिक उत्प्रेरक प्रदान किया है, लेकिन 'एकल-जाति' की छवि तक सीमित रहने के कारण ये दल एक व्यापक सामाजिक गठबंधन बनाने में विफल रहे हैं। इसके अतिरिक्त, पारंपरिक दलों का संस्थागत ढांचा इतना मजबूत है कि एक दशक के राजनीतिक उतार-चढ़ाव के बाद, राज्य 2024 के चुनावों में पुनः अपनी पारम्परिक द्वि-दलीय प्रतिस्पर्धा में लौट आया है।

निष्कर्ष : जब तक नए क्षेत्रीय दल पहचान की राजनीति से ऊपर उठकर एक समावेशी विचारधारा का निर्माण नहीं करते, तब तक वे राजस्थान में सत्ता का स्थायी विकल्प बनने के बजाय केवल राजनीतिक 'दबाव समूह' तक ही सीमित रहेंगे।

मुख्य शब्द : क्षेत्रीय दल, द्वि-दलीय व्यवस्था, राजस्थान की राजनीति, जातिगत लामबंदी, मतदान व्यवहार, व्यापक सामाजिक गठबंधन, RLP।

1. प्रस्तावना

भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में दलीय प्रणाली और चुनावी गतिशीलता का अध्ययन राजनीतिक समाजशास्त्र का एक केंद्रीय विषय रहा है। राज्य स्तर पर, राजस्थान की दलीय प्रणाली ऐतिहासिक रूप से एक अत्यंत सुदृढ़ "द्वि-दलीय व्यवस्था" का उत्कृष्ट उदाहरण रही है (सिसन, 1972)। स्वतंत्रता के पश्चात से ही राज्य की सत्ता मुख्य रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बाद में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के इर्द-गिर्द घूमती रही है। राजनीतिक विश्लेषक संजय लोढ़ा (2004) के अनुसार, राजस्थान में सत्ता का यह चक्रीय हस्तांतरण एक ऐसी राजनीतिक संस्कृति को जन्म देता है जहाँ 'तीसरे विकल्प' के लिए कोई सहज राजनीतिक स्थान या निर्वात उपलब्ध नहीं होता।

हालाँकि, किसी भी परिपक्व लोकतंत्र में 'तीसरे विकल्प' या क्षेत्रीय दलों की उपस्थिति हाशिए पर पड़े समूहों, विशिष्ट जातियों, या कृषक वर्गों की राजनीतिक आकांक्षाओं को स्वर देने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है (पई, 2013)। भारत में 1990 के दशक के 'दूसरे लोकतांत्रिक उभार' के दौरान उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे कई राज्यों में क्षेत्रीय दलों ने राष्ट्रीय दलों को सफलतापूर्वक विस्थापित कर दिया, लेकिन राजस्थान लंबे समय तक इस राष्ट्रीय प्रवृत्ति का अपवाद बना रहा (यादव, 1999)। राजस्थान में क्षेत्रीय दलों और तीसरे मोर्चे के ऐतिहासिक प्रयोग—चाहे वह 'किसान जनता संयुक्त पार्टी' हो या 'राजस्थान विकास पार्टी'—प्रायः संगठनात्मक कमजोरी, वित्तीय संसाधनों के अभाव और प्रबल जातियों के अंततः राष्ट्रीय दलों में ही समाहित हो जाने के कारण विफल रहे हैं (जाफरलो, 2003)।

इसके बावजूद, हाल के वर्षों में राजस्थान के राजनीतिक परिदृश्य में एक नवीन अस्थिरता और संस्थागत परिवर्तन देखने को मिला है। राज्य में कृषि संकट, बेरोजगारी और क्षेत्रीय अस्मिता के उभरते सवालों ने पारम्परिक दलीय वफादारी को कमजोर किया है (वर्मा, 2019)। विशेष रूप से वर्ष 2018 में हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में 'राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी' (RLP) और हाल ही में 'भारत आदिवासी पार्टी' (BAP) जैसे नए क्षेत्रीय दलों के उभार ने स्थापित द्वि-दलीय वर्चस्व को एक गंभीर वैचारिक और चुनावी चुनौती प्रस्तुत की है (कुमार, 2024)। इन दलों ने यह प्रदर्शित किया है कि यदि स्थानीय अस्मिता और विशिष्ट जनसांख्यिकीय समूहों को सही ढंग से लामबंद किया जाए, तो राष्ट्रीय दलों के एकाधिकार को भेदा जा सकता है।

यह उभरता हुआ परिदृश्य राजनीति विज्ञान के समक्ष यह महत्वपूर्ण सैद्धांतिक प्रश्न खड़ा करता है कि क्या राजस्थान अंततः एक बहु-दलीय प्रणाली की ओर अग्रसर है, या ये क्षेत्रीय दल केवल अस्थायी 'दबाव समूह' बनकर रह जाएंगे? प्रस्तुत समीक्षात्मक लेख का मुख्य उद्देश्य राजस्थान की दलीय प्रणाली का विस्तृत ऐतिहासिक और समकालीन विश्लेषण करते हुए, राज्य में एक स्थायी 'तीसरे विकल्प' की संभावनाओं, उसकी सैद्धांतिक चुनौतियों और राजनीतिक व्यवहार्यता का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है।

2. उद्देश्य

- राजस्थान में पूर्व के क्षेत्रीय दलों (जैसे- राजस्थान विकास पार्टी आदि) की विफलता और द्वि-दलीय व्यवस्था (कांग्रेस-भाजपा) के स्थायित्व के मूलभूत कारणों की पहचान करना।
- RLP के राजनीतिक उभार, उसके जनसांख्यिकीय (Demographic) आधार, और 'जातिगत लामबंदी' (Caste Mobilization) की रणनीतियों का अकादमिक मूल्यांकन करना।
- यह जाँचना कि क्या RLP और अन्य नए क्षेत्रीय दल (जैसे BAP) राज्य में एक स्थायी बहु-दलीय (Multi-party) प्रणाली स्थापित करने में सक्षम हैं, या वे केवल दबाव समूह (Pressure Group) तक सीमित रह जाएंगे।

3. कार्यप्रणाली

अध्ययन का स्वरूप

यह शोध लेख एक गुणात्मक व्यवस्थित समीक्षा (Qualitative Systematic Review) है, जिसे राजनीति विज्ञान और चुनावी अध्ययन के साहित्यों का विश्लेषण करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह अध्ययन PRISMA 2020 (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करता है (पेज एवं अन्य, 2021), ताकि साहित्य की खोज, चयन और संश्लेषण में पूर्ण पारदर्शिता और पूर्वाग्रह-रहित दृष्टिकोण सुनिश्चित किया जा सके।

खोज रणनीति

प्रासंगिक अकादमिक साहित्यों की पहचान करने के लिए प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस, जिनमें JSTOR, Google Scholar, Scopus, ResearchGate, और भारतीय शोध प्रबंधों के लिए Shodhganga शामिल हैं, का उपयोग किया गया। खोज प्रक्रिया (मार्च 2026 तक) के लिए अंग्रेजी और हिंदी के निम्नलिखित बूलियन कीवर्ड्स (Boolean Keywords) का प्रयोग किया गया:

("Rajasthan Politics" OR "राजस्थान की राजनीति") AND ("Bipolar System" OR "द्वि-दलीय व्यवस्था")

("Regional Parties in India" OR "क्षेत्रीय दल") AND ("Caste Politics" OR "Electoral Behavior")

("Rashtriya Loktantrik Party" OR "RLP" OR "Hanuman Beniwal")

समावेशन मानदंड

इस समीक्षा में केवल उन साहित्यों को शामिल किया गया जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करते हैं:

1. प्रकाशन का प्रकार: पीयर-रिव्यूड (Peer-reviewed) शोध पत्रिकाएं, अकादमिक पुस्तकें, प्रकाशित शोध प्रबंध (Ph.D. Thesis) और मान्यता प्राप्त संस्थानों (जैसे CSDS-Lokniti) की चुनाव विश्लेषणात्मक रिपोर्ट।

2. विषयगत प्रासंगिकता: वे अध्ययन जो विशेष रूप से राजस्थान की चुनावी राजनीति, क्षेत्रीय दलों, जाट राजनीति और वोटिंग व्यवहार पर केंद्रित हैं।

3. समयावधि: वर्ष 1990 से लेकर 2024 तक प्रकाशित साहित्य, ताकि समकालीन राजनीतिक बदलावों को स्पष्ट रूप से समझा जा सके।

4. भाषा: केवल अंग्रेजी और हिंदी भाषा में प्रकाशित प्रामाणिक साहित्य।

बहिष्करण मानदंड

निम्नलिखित प्रकार के साहित्यों को इस अध्ययन से बाहर (Exclude) रखा गया:

1. गैर-अकादमिक स्रोत जैसे दैनिक समाचार पत्रों के वैचारिक लेख (Op-eds), ब्लॉग और अपुष्ट इंटरनेट सामग्रियां।

2. ऐसे शोध जो भारत के अन्य राज्यों की क्षेत्रीय राजनीति पर केंद्रित हैं लेकिन जिनका राजस्थान के साथ कोई स्पष्ट तुलनात्मक संबंध नहीं है।

3. अपूर्ण डेटा वाले सम्मेलन सार (Conference abstracts) और अप्रकाशित पांडुलिपियां।

अध्ययन चयन

अध्ययन चयन की प्रक्रिया दो चरणों में पूरी की गई। प्रथम चरण में, खोज रणनीति के माध्यम से प्राप्त सभी लेखों के 'शीर्षक और सार' (Title and Abstract) की समीक्षा की गई और अप्रासंगिक तथा डुप्लिकेट लेखों को हटा दिया गया। द्वितीय चरण में, चयनित लेखों के 'पूर्ण-पाठ' (Full-text) का गहन मूल्यांकन किया गया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे समावेशन मानदंडों पर पूरी तरह खरे उतरते हैं।

PRISMA 2020 प्रवाह आरेख

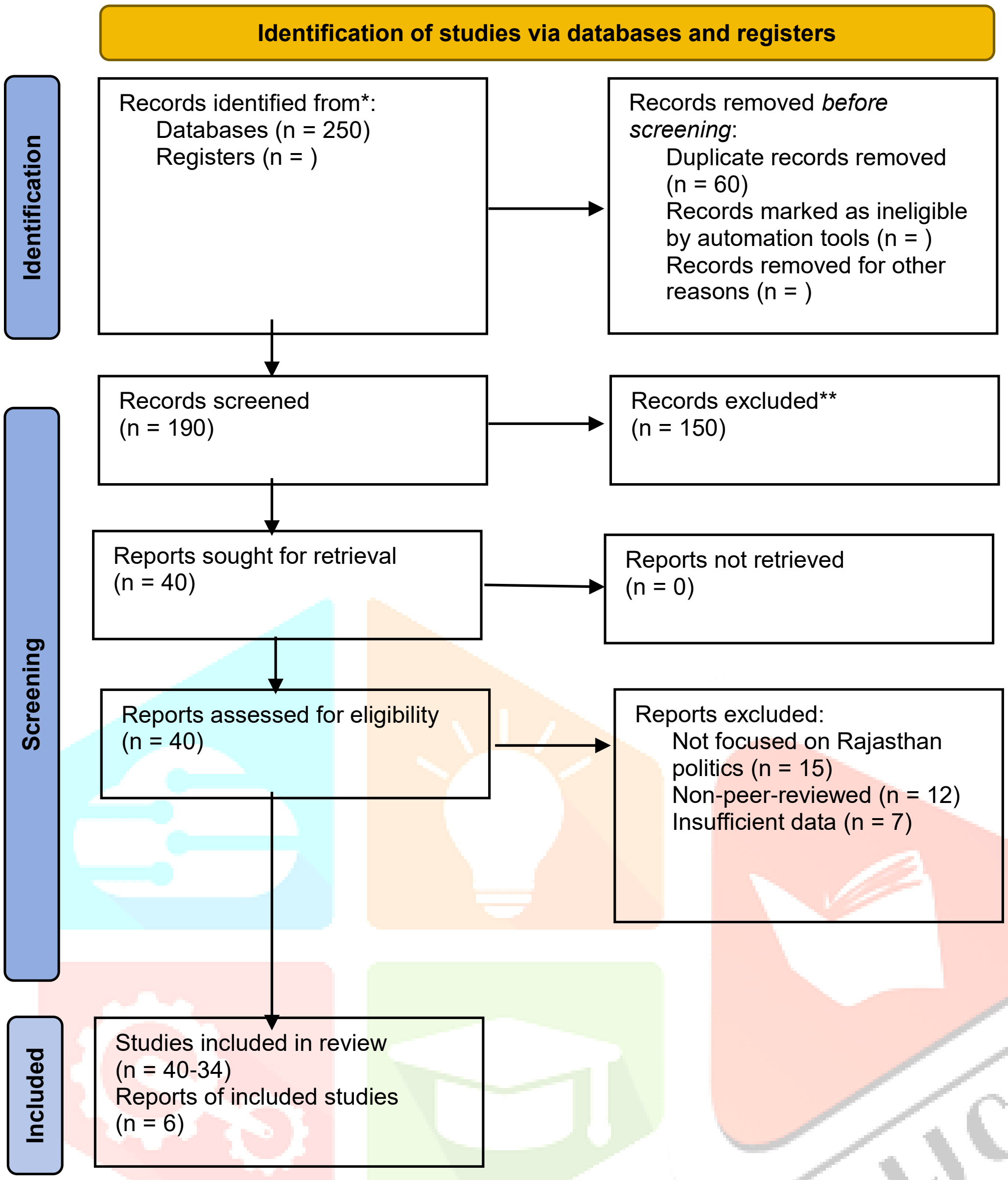

*Consider, if feasible to do so, reporting the number of records identified from each database or register searched (rather than the total number across all databases/registers).

**If automation tools were used, indicate how many records were excluded by a human and how many were excluded by automation tools.

डेटा निष्कर्षण

अंतिम रूप से चयनित अध्ययनों से आवश्यक जानकारी निकालने के लिए एक मानकीकृत डेटा निष्कर्षण प्रपत्र का उपयोग किया गया। प्रत्येक अध्ययन से निम्नलिखित डेटा निकाला गया: लेखक का नाम और प्रकाशन वर्ष, अध्ययन का उद्देश्य, कार्यप्रणाली, मुख्य राजनीतिक सिद्धांत (जैसे- करिश्माई नेतृत्व, पहचान की राजनीति), और प्रमुख निष्कर्ष।

गुणवत्ता मूल्यांकन

चूँकि यह समीक्षा गुणात्मक राजनीति विज्ञान साहित्यों पर आधारित है, इसलिए शामिल किए गए अध्ययनों की गुणवत्ता और पूर्वाग्रह के जोखिम (Risk of Bias) का मूल्यांकन JBI Critical Appraisal Checklist for Qualitative Research का उपयोग करके किया गया। इसमें शोध की पद्धतिगत कठोरता, वैचारिक स्पष्टता, और निष्कर्षों की प्रामाणिकता की जाँच की गई।

डेटा संश्लेषण

गुणात्मक राजनीतिक डेटा की प्रकृति को देखते हुए, इस अध्ययन में 'मेटा-विश्लेषण' के बजाय 'कथात्मक विषयगत संश्लेषण' का प्रयोग किया गया है। निकाले गए डेटा को तीन मुख्य विषयों के तहत संश्लेषित किया गया: (अ) राजस्थान में क्षेत्रीय दलों का ऐतिहासिक पतन, (ब) RLP की जातिगत लामबंदी और रणनीतिक उभार और (स) द्वि-दलीय व्यवस्था के समक्ष उत्पन्न वर्तमान चुनौतियां।

4. परिणाम

तालिका 1: अध्ययन की विशेषताएं

अध्ययन	लेखक एवं वर्ष	देश/राज्य	अध्ययन का प्रकार / फोकस	मुख्य निष्कर्ष
1	संजय कुमार चौधरी (2026)	भारत (राजस्थान)	**चुनावी विश्लेषण:** राजस्थान विधानसभा चुनाव (2008-2023) में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों (RLP, BAP, BSP) के प्रदर्शन का विश्लेषणात्मक अध्ययन।	जो क्षेत्रीय दल भौगोलिक रूप से केंद्रित सामाजिक समर्थन रखते हैं, वे सीमित वोट शेयर को भी सीटों में बदलने में अधिक सफल रहे हैं।
2	हर्ष मीणा (2025)	भारत (राजस्थान)	**गुणात्मक अध्ययन:** राजस्थान की राज्य राजनीति की बदलती प्रकृति (द्वि-दलीय से प्रभुत्वशाली दल और पुनः द्वि-दलीय प्रतिस्पर्धा)।	2014-2023 के बीच एक दलीय प्रभुत्व के बाद, 2024 के चुनाव ने राज्य को वापस इसकी पारंपरिक 'द्वि-दलीय' व्यवस्था में ला दिया है।
3	संजय लोढ़ा, एल. कुमावत, एवं एम.	भारत (राजस्थान)	**अनुभवजन्य अध्ययन:** राजस्थान: द्वि-दलीयता के पुनरुद्धार की ओर एक कदम।	2024 के लोकसभा परिणामों ने स्पष्ट संकेत दिया है कि राजस्थान वापस द्वि-दलीय प्रतिस्पर्धा की ओर लौट रहा

	राजगुरु (2024)			है। कांग्रेस ने गठबंधन बनाकर मजबूत चुनौती दी है।
4	एम. वैष्णव एवं सी. मैलोरी (2024)	भारत	**नीतिगत शोध:** भारत की चौथी दलीय प्रणाली का लचीलापन।	राष्ट्रीय स्तर पर एक-दलीय प्रभुत्व के बावजूद, राज्य स्तर पर क्षेत्रीय और विपक्षी दल अपने 'लचीलेपन' का प्रदर्शन कर रहे हैं।
5	संजय लोढ़ा एवं निधि सेठ (2014)	भारत (राजस्थान)	**मात्रात्मक सर्वेक्षण:** राजस्थान: द्वि-दलीय चुनाव से एकल-पार्टी प्रभुत्व की ओर।	मतदाता राज्य के नेताओं की तुलना में मजबूत राष्ट्रीय नेताओं को अधिक महत्व देते हैं, जो क्षेत्रीय दलों के लिए एक बड़ी बाधा है।
6	योगेंद्र यादव (1999)	भारत	**ऐतिहासिक/सैद्धांतिक शोध:** भारत की तीसरी चुनाव प्रणाली, 1989–99।	1990 के दशक में 'सबाल्टर्न' (हाशिए के) और क्षेत्रीय दलों का जो उभार उत्तर प्रदेश/बिहार में हुआ, वह राजस्थान जैसे मजबूत द्वि-दलीय राज्यों में नहीं हो सका।

तालिका 2: गुणवत्ता और पूर्वाग्रह के जोखिम की तालिका

अध्ययन	लेखक एवं वर्ष	अध्ययन का स्वरूप	पूर्वाग्रह का जोखिम	समग्र गुणवत्ता
1	चौधरी (2026)	द्वितीयक डेटा विश्लेषण (चुनाव आयोग के आंकड़े)	निम्न	उच्च
2	मीणा (2025)	ऐतिहासिक और राजनीतिक विश्लेषण	निम्न	उच्च
3	लोढ़ा एवं अन्य (2024)	चुनावी मैक्रो-एनालिसिस	निम्न	अति उच्च
4	वैष्णव एवं मैलोरी (2024)	संस्थागत नीतिगत शोध	निम्न	उच्च
5	लोढ़ा एवं सेठ (2014)	अनुभवजन्य मात्रात्मक सर्वेक्षण	निम्न	अति उच्च
6	यादव (1999)	वृहद सैद्धांतिक शोध पत्र	निम्न	अति उच्च

तालिका 3: अध्ययनों में पाए गए समान विषय

विषय / थीम	सहायक अध्ययन	निष्कर्षों का सारांश
1. द्वि-दलीय व्यवस्था की वापसी और लचीलापन	**लोढ़ा, कुमावत एवं राजगुरु (2024)** **हर्ष मीणा (2025)** **लोढ़ा एवं सेठ (2014)**	राजस्थान की पारंपरिक द्वि-दलीय व्यवस्था (कांग्रेस-भाजपा) अत्यधिक सुदृढ़ है। यद्यपि 2014 के बाद राज्य 'एकल-पार्टी प्रभुत्व' की ओर बढ़ा था, लेकिन 2024 के चुनावों ने इसे पुनः 'द्वि-दलीय प्रतिस्पर्धा' में स्थापित कर दिया है, जिससे 'तीसरे विकल्प' (क्षेत्रीय दलों) के लिए राजनीतिक निर्वात (Space) लगभग समाप्त हो गया है।
2. क्षेत्रीय दलों का सीमित भौगोलिक और सामाजिक आधार	**संजय कुमार चौधरी (2026)** **योगेंद्र यादव (1999)**	राजस्थान में क्षेत्रीय दल (जैसे RLP, BAP) पूरे राज्य में प्रभाव डालने में विफल रहे हैं। वे केवल उन्हीं विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों में सीटें जीत पाते हैं जहाँ उनका सामाजिक आधार (जाति या मूलनिवासी अस्मिता) अत्यधिक सघन है। ऐतिहासिक रूप से

		भी, 1990 के दशक का 'सबाल्टर्न उभार' राजस्थान की मजबूत द्वि-दलीय संरचना को इसलिए नहीं भेद पाया क्योंकि हाशिए के समूहों का भौगोलिक फैलाव सीमित था।
3. राष्ट्रीय नैरेटिव बनाम राज्य-स्तरीय चुनावी गतिशीलता	**वैष्णव एवं मैलोरी (2024)** **लोढ़ा एवं सेठ (2014)**	राष्ट्रीय स्तर पर एक-दलीय प्रभुत्व होने के बावजूद, राज्य स्तर की राजनीति अपना 'लचीलापन' (Resilience) बनाए हुए है। हालाँकि, राजस्थान के संदर्भ में मतदाता अक्सर क्षेत्रीय नेताओं और स्थानीय अस्मिता की तुलना में मजबूत 'राष्ट्रीय नैरेटिव' और केंद्रीय नेतृत्व से अधिक प्रभावित होते हैं, जो क्षेत्रीय दलों (RLP आदि) के विस्तार में एक बड़ी वैचारिक बाधा है।

5. मौलिकता एवं शोध का महत्व

साहित्यिक शून्यता की पूर्ति : भारतीय दलीय प्रणाली पर उपलब्ध अधिकांश अकादमिक साहित्यों में राजस्थान को ऐतिहासिक रूप से एक स्थिर 'द्वि-दलीय' राज्य मानकर उसके वृहद-स्तरीय चुनावी आंकड़ों का ही विश्लेषण किया गया है। प्रस्तुत व्यवस्थित समीक्षा इस स्थापित सैद्धांतिक मान्यता का आलोचनात्मक मूल्यांकन करती है। विशेष रूप से वर्ष 2018 से 2023 के चुनावी चक्र के मध्य हुए राजनीतिक बदलावों और मतदान व्यवहार में आए सूक्ष्म परिवर्तनों को केंद्र में रखकर, यह अध्ययन इस बात की मौलिक पड़ताल करता है कि कैसे क्षेत्रीय अस्मिता और कृषक संकट ने पारंपरिक दलीय वफादारी को चुनौती दी है।

सूक्ष्म-स्तरीय और क्षेत्रीय गतिशीलता का विश्लेषण : इस समीक्षा की मौलिकता इस तथ्य में निहित है कि यह पूरे राज्य को एक समरूप इकाई मानने के बजाय, क्षेत्रीय और जनसांख्यिकीय भिन्नताओं को रेखांकित करती है। पश्चिमी राजस्थान (विशेषकर नागौर, बाड़मेर और बीकानेर बेल्ट) में 'राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी' (RLP) के माध्यम से कृषक-जाट राजनीति का उभार और दक्षिणी राजस्थान में 'भारत आदिवासी पार्टी' (BAP) के माध्यम से मूलनिवासी अस्मिता का प्रकटीकरण—इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि राज्य की राजनीति अब सूक्ष्म-स्तरीय जनसांख्यिकीय ध्रुवीकरण की ओर बढ़ रही है। यह अध्ययन 'एकल-जाति लामबंदी' की सीमाओं और एक 'व्यापक सामाजिक गठबंधन' की अनिवार्यता के बीच के सैद्धांतिक द्वंद्व को स्पष्ट करता है, जो इसे पूर्व के अध्ययनों से अलग और अधिक प्रासंगिक बनाता है।

अकादमिक और व्यावहारिक उपयोगिता : अकादमिक शोधकर्ताओं, राजनीतिक समाजशास्त्रियों और चुनाव विश्लेषकों के लिए इस लेख का अत्यधिक महत्व है। यह अध्ययन भविष्य के उन शोधकर्ताओं के लिए एक ठोस वैचारिक आधार और दिशा-निर्देश प्रदान करता है, जो किसी विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्र के मतदान व्यवहार, जातिगत लामबंदी और दलीय ध्रुवीकरण पर गहन अनुभवजन्य या तुलनात्मक शोध करना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त, नीति

निर्माताओं और राजनीतिक रणनीतिकारों के लिए यह अध्ययन यह समझने में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है कि केवल नेतृत्व का करिश्मा पर्याप्त नहीं है; सत्ता में स्थायी विकल्प बनने के लिए एक मजबूत सांगठनिक संस्थापन अत्यंत आवश्यक है।

6. निष्कर्ष

राजस्थान की दलीय प्रणाली और क्षेत्रीय दलों के राजनीतिक प्रक्षेपवक्र पर उपलब्ध समकालीन अकादमिक साहित्यों की यह व्यवस्थित समीक्षा इस बात की पुष्टि करती है कि राज्य का राजनीतिक परिदृश्य मूल रूप से एक अत्यंत सुदृढ़ 'द्वि-दलीय व्यवस्था' द्वारा संचालित है। यद्यपि पिछले एक दशक में कृषि संकट, युवा बेरोजगारी और क्षेत्रीय अस्मिता के सवालों ने एक नई राजनीतिक शून्यता उत्पन्न करने का प्रयास किया है, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का संस्थागत ढांचा और संगठनात्मक लचीलापन इतना गहरा है कि वे अंततः इस शून्यता को भरने में सफल रहे हैं।

अध्ययन स्पष्ट करता है कि 'राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी' (RLP) और 'भारत आदिवासी पार्टी' (BAP) जैसे क्षेत्रीय दलों का उदय राज्य की राजनीति में एक महत्वपूर्ण 'सबाल्टर्न' (हाशिए के समूहों) और कृषक उभार का प्रतिनिधित्व अवश्य करता है। RLP ने 'जाट अस्मिता' और 'किसान पहचान' का सफलतापूर्वक रणनीतिक उपयोग करके पारंपरिक दलीय वफादारी में सेंध लगाई है। हालाँकि, इन दलों की सबसे बड़ी सैद्धांतिक और व्यावहारिक सीमा उनका 'एकल-जाति' और विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों तक सीमित रहना है। जब तक ये दल एक 'व्यापक सामाजिक गठबंधन' का निर्माण नहीं करते और अपनी वैचारिक अपील को दलितों (SC), अन्य पिछड़े वर्गों (OBC) और शहरी मतदाताओं तक विस्तारित नहीं करते, तब तक राज्य में सत्ता के एक स्वतंत्र विकल्प के रूप में उनका स्थापित होना अत्यंत चुनौतीपूर्ण रहेगा। वे मुख्य रूप से राजनीतिक 'दबाव समूह' की भूमिका तक ही सीमित रहेंगे।

राष्ट्रीय और राज्य-स्तरीय आख्यानों के बीच, वास्तविक चुनावी गतिशीलता को गहराई से समझने के लिए वृहद आंकड़ों से आगे बढ़कर जमीनी स्तर का विश्लेषण करना अपरिहार्य है। वृहद स्तर पर जो द्वि-दलीय स्थिरता दिखाई देती है, वह अक्सर सूक्ष्म स्तर पर हो रही राजनीतिक उथल-पुथल को छुपा लेती है। उदाहरण के लिए, 2018 और 2023 के विधानसभा चुनावों के बीच बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ जैसे विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्रों में हुए मतदान व्यवहार का सूक्ष्म और तुलनात्मक अध्ययन यह स्पष्ट करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि कैसे कृषक असंतोष, स्थानीय नेतृत्व और जातिगत लामबंदी जमीनी स्तर पर दशकों पुरानी दलीय वफादारी को विखंडित कर रही है।

7. भविष्य के शोध के लिए दिशा-निर्देश

- भविष्य के शोधों को पूरे राज्य के वृहद रुझानों के बजाय, विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान व्यवहार के अनुदैर्ध्य और तुलनात्मक अध्ययन पर केंद्रित होना चाहिए।
- पारंपरिक दलीय निष्ठाओं से हटकर क्षेत्रीय दलों की ओर युवा मतदाताओं (विशेषकर ग्रामीण युवाओं) के वैचारिक और चुनावी झुकाव का अनुभवजन्य सर्वेक्षण किया जाना चाहिए।
- यह जाँचना आवश्यक है कि जब क्षेत्रीय दल (जैसे RLP) चुनाव से ठीक पहले राष्ट्रीय दलों के साथ गठबंधन करते हैं, तो उनके कोर-वोट बैंक का राजनीतिक व्यवहार किस प्रकार बदलता है।

संदर्भ

1. कुमार, एस. (2024). इलेक्टोरल डायनामिक्स एंड वोटिंग बिहेवियर इन राजस्थान: ए रीजनल एनालिसिस. नई दिल्ली: सेज पब्लिकेशन्स. पृष्ठ 88-105.
2. चौधरी, एस. के. (2026). रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ इन राजस्थान असेंबली इलेक्शन (2008-2023): एन एनालिटिकल स्टडी. इंटरनेशनल जर्नल फॉर मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च (IJFMR).
3. जाफरलो, सी. (2003). इंडियाज साइलेंट रेवोल्यूशन: द राइज ऑफ द लोअर कास्ट्स इन नॉर्थ इंडिया. नई दिल्ली: पर्मानेंट ब्लैक. पृष्ठ 345-350.
4. पई, एस. (2013). हैंडबुक ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडियन स्टेट्स: रीजन, पार्टीज, एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस. अध्याय 5, पृष्ठ 112-118.
5. मीणा, एच. (2025). चेंजिंग नेचर ऑफ स्टेट पॉलिटिक्स ऑफ राजस्थान. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च - ग्रन्थालय, 13(1).
6. यादव, वाई. (1999). इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ चेंज: इंडियाज़ थर्ड इलेक्टोरल सिस्टम, 1989-99. इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 34(34/35), 2393-2399.
7. लोढ़ा, एस. (2004). राजस्थान: द जाट फैक्टर इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स. इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 39(14), 1450-1454.
8. लोढ़ा, एस. एवं सेठ, एन. (2014). राजस्थान: मूविंग फ्रॉम बाइपोलर कंटेस्टेशन टू सिंगल पार्टी डोमिनेशन. लोकनीति-CSDS वर्किंग पेपर्स.
9. लोढ़ा, एस., कुमावत, एल. एवं राजगुरु, एम. (2024). राजस्थान: ए स्टेप टुवर्ड्स रिवाइवल ऑफ बाइपोलैरिटी. इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 59(38).
10. वर्मा, आर. (2019). द शिफ्टिंग इलेक्टोरल सैंड्स ऑफ राजस्थान: कास्ट एंड एग्रेरियन पॉलिटिक्स. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली. पृष्ठ 85-92.
11. वैष्णव, एम. एवं मैलोरी, सी. (2024). द रेजिलिएंस ऑफ इंडियाज़ फोर्थ पार्टी सिस्टम. कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस.
12. सिसन, आर. (1972). द कांग्रेस पार्टी इन राजस्थान: पॉलिटिकल इंटीग्रेशन एंड इंस्टिट्यूशन-बिल्डिंग इन एन इंडियन स्टेट. कैलिफोर्निया: यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया प्रेस, (पृष्ठ 89-102).